stages. In the case of formulations, exemptions are extended to make essential and life-saving drugs available. In extending such duty exemptions, various factors such as, essential nature of these drugs, indigenous availability, estimated demand and the price structure etc. are taken into account.

(d) Names of finished medicines and bulk drugs which are subjected to price control under the Drugs (Prices Control) Order, 1987, and amendments thereto, issued from time to time are notified in the Official Gazette. Notifications wherein finished medicines, bulk drugs and intermediates have been either exempted or subjected to concessional rates of import duty, issued during the last three years have also been notified in the Official Gazette and have been duly laid on the Table of the House.

The bulk drugs and the finished medicines for which exemption/concessions in import duty have been given, but which are not subjected to any price control can be ascertained by reference to the Drugs (Prices Control) Order, 1987, and the amendments thereto.

(e) to (g) Certain proposals for increase in the import duties on some bulk drugs, intermediates and finished medicines, have been considered in the recent past. However, as a general policy decision, it was decided not to increase the import duties on any drugs, drug intermediates and finished medicines for the present, keeping in view the recent exchange rate adjustment of the rupee which has resulted in an increase in the price of imported drugs. The foreign exchange involved due the continuation of the duty exemptions on these products is not quantifiable.

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशनों के बारे में जाफरी समिति की समुक्तियां

1178. **मौलवी अबैदुल्ला खान आजमी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाफरी समिति ने एन०सी०ई० आर०टी० द्वारा उर्दू पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण के बारे में क्या-क्या समुक्तियां और सिफारिशें की हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है ;

(ग) क्या अब तक कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) उर्दू की प्रोन्नति के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए (जाफरी समिति) ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

"समिति यह भी महसूस करती है कि सरकार को स्कूली बच्चों के लिए उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने में होने वाले विलम्ब की जांच करनी चाहिए । इस समय जबकि इन पाठ्य-पुस्तकों का अनुवाद उर्दू तरक्की ब्यूरो द्वारा किया जाता है तथा ये रा०शै०अनु०प्र०प० द्वारा प्रकाशित की जाती हैं । प्रत्येक वर्ष इस आशय की शिकायतें होती हैं कि कुछ पाठ्य पुस्तकें तो बिल्कुल उपलब्ध ही नहीं होती हैं जबकि कुछ अन्य पुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं । सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए तथा उर्दू भाषी जनता की इस विशिष्ट शिकायत को दूर करने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय करने चाहिए ।"

(ग) से (ङ०) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उर्दू की पुस्तकों के प्रकाशन और संवितरण में होने वाले विलम्ब की समस्या की जांच की गई है । हिन्दी अंग्रेजी की पुस्तकों और उर्दू की पुस्तकों में समयांतराल के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) हिन्दी/अंग्रेजी में आरम्भ में तैयार की गई पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद हिन्दी/अंग्रेजी के पुस्तकों के तैयार हो जाने के बाद ही हो सकता है ; (ii) पुस्तकों के उर्दू अनुवाद और पुनरीक्षण प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 6 माह का समय लग जाता है ; तथा (iii) पुस्तक के अनुदित पाठ का मुलेख तैयार किया जाता है । यह चूंकि हाथ से तैयार किया जाता है, अतः इसमें काफी समय लग जाता है । तथापि पुस्तकों के हिन्दी/अंग्रेजी रूपांतर और उर्दू पुस्तकों के प्रकाशन में व्याप्त समयांतराल को कम करने के लिए रा०शै०अनु०प्र०प० तथा उर्दू डेस्क की ब्यूरो को उन क्षेत्रों का पता लगाने की सलाह दी गई है जहां इस समस्या के समाधान के लिए सुधार किया जा सकता है ।

Centrally Sponsored Sports Infrastructural projects in Karnataka

1179. **SHRI J. P. JAVALI:** Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some sports infrastructural projects assisted by Central Government are under implementation in the State of Karnataka;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Karnataka Government has also sent any fresh proposals for new projects; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS) WITH ADDITIONAL CHARGE OF DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT (KUM. MAMATA BANERJEE): (a) Yes, Sir.

(b) The details of sports infrastructure projects sanctioned are as under:

No. of projects approved	Central assistance sanctioned	No. of projects completed
81	Rs. 1,45,29,280/-	17

(c) Yes, Sir.

(d) Government of Karnataka forwarded following fresh proposals during the last 3 years:—

1988-89	27	proposals
1989-90	12	proposals
1990-91	11	proposals
TOTAL	50	proposals

These could not be considered earlier because the Department has, as a matter of policy decided, not to entertain fresh proposals when a large number of projects are remaining incomplete.

Merger of regional rural banks with Nationalised banks

1180. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to merge regional rural banks with the sponsoring nationalised banks;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when a decision is likely to be taken in this regard?